



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 664]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 2016/भाद्र 31, 1938

No. 664]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2016/ BHADRA 31, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2016

सं. 41/2016- सेवा कर

सा.का.नि. 902 (अ).- वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा, राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगम/ प्रतिष्ठानों के द्वारा औद्योगिक भूखण्डों को लंबे समय तक (30 वर्ष या इससे अधिक) पट्टे पर देने के माध्यम से जो कर वाली सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उनको उक्त अधिनियम की धारा 66 ख के अंतर्गत लगाये जाने वाले सेवाकर से उस हद तक सेवाकर से छूट प्रदान करती है जिस हद तक ये ऐसे पट्टे के लिए भुगतान किये गये या किए जाने वाले एकबारगी राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, मूल्य, विकास प्रभार या अन्य किसी भी नाम से जाना जाता है) पर देय है।

[ फा. सं. 354/51/2016-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2016

**No. 41/2016 – Service Tax**

**G.S.R. 902(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts taxable service provided by State Government Industrial Development Corporations/ Undertakings to industrial units by way of granting long term (thirty years, or more) lease of industrial plots from so much of service tax leviable thereon under section 66B of the said Act, as is leviable on the one time upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name) payable for such lease.

[F. No. 354/51/2016 –TRU]  
ANURAG SEHGAL, Under Secy.